

(घ) क्या सरकार दिल्ली में एल. पी. जी. सिलेण्डरों की मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एल.पी.जी. सिलेण्डरों की वर्तमान वितरण प्रणाली और सुधार करने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला धुलाई कारखानों में विद्युत का अभाव

635. श्री रणजीत सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला धुलाई कारखानों में विद्युत के अभाव के कारण उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो 1990-91 के वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1991 के अंत तक इन धुलाई कारखानों के उत्पादन आंकड़े क्या थे;

(ग) क्या पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में उत्पादन कम हुआ है; और

(घ) इन धुलाई कारखानों की मासिक विद्युत जरूरत कितनी है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी, 1991 के अंत तक मासिक विद्युत उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह काबड़ो) :

(क) जी, हाँ। विद्युत की कमी का वाणरियों के कार्य निष्पादन पर, विशेषकर भारत कोकिंग कोल लि० की वाणरियों पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) वाणरियों द्वारा अप्रैल-जनवरी, 1990-91 तथा अप्रैल-जनवरी, 1989-90 की अवधि में हुआ उत्पादन और इस संबंध में उत्पादन में आए अन्तराल को विवरण के रूप में नीचे दिया गया है :—

विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

नाम	अप्रैल-जनवरी		अन्तराल
	1990-91 (अनंतिम)	1989-90	
दुग्दा-I	459	443	(+) 16
दुग्दा-II	473	459	(+) 14
भोजूडीह	844	832	(+) 12
पायरडीह	336	434	(-) 98
लोडना	136	138	(-) 2
सुदामडीह	351	431	(-) 80
बरोरा	36	63	(-) 27
मुनीडीह	288	367	(-) 79
मज्झा	38	44	(-) 6
जोड़ भा०को०को०लि०	2961	3211	(-) 250

1	2	3	4
कारगली	971	901	(+) 70
कथारा	494	593	(-) 99
सर्वांग	515	572	(-) 57
बिडी	616	577	(+) 39
*राजस्थान	191	538	(+) 253
कुल से०को०लि०	3387	3181	(+) 206
नंदन (के०को०लि०)	300	255	(+) 45
कुल को०इ०लि०	6648	6647	(+) 1

*वर्ष 1989-90 के दौरान निरीक्षणाधीन के अंतर्गत चालू किया गया ।

(घ) इस संबंध में यथा संभव सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तकनीकी शिक्षा का विकास और विस्तार

636. श्री राम जेठ मलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कोई परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान इस परियोजना के प्रथम चरण में कुल कितने नये तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा क्या उनके खोले जाने

के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां 1990-91 के दौरान ये संस्थान खोले जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय) : (क) से (ङ) देश में तकनीशियन (पॉलिटेक्निक) शिक्षा का स्तरोन्नयन करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से सरकार द्वारा एक परियोजना आरम्भ की गई है। मुख्य रूप से यह राज्य क्षेत्र की एक ऐसी परियोजना है जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के प्रथम (1990-1997) चरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विकास की उनकी प्राथमिकताओं, स्थानीय आवश्यकताओं, विद्यमान सुविधाओं, जनशक्ति, अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के द्वारा अनेक नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तथापि, वर्ष 1990-91 के दौरान